

उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

क्र. डी-2454.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 122 एवं धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-चार, दिनांक 12 अगस्त, 2022 में, उक्त संहिता की धारा 122 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 27 में उप-नियम (1) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात् :-

सारणी

| अनुक्रमांक (1) | प्रकरण की प्रकृति (2) | मानदेय (3) |
|-------------------|--|---|
| 1. | मध्यस्थता के माध्यम से समझौता होने पर | रुपए 5000/- प्रति प्रकरण |
| 2. | संबद्ध प्रकरण | रुपए 1000/- प्रति प्रकरण, अधिकतम रुपए 3000/- के अध्यक्षीन रहते हुए (चाहे संबद्ध प्रकरणों की संख्या कितनी भी हो) |
| 3. | कोई समझौता न होने की दशा में (तीन प्रभावी सुनवाईयों के बावजूद पक्षकारों के किसी सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में असफल रहने की दशा में) | रुपए 2500 रुपए |

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 28th October 2022

No.D-2454.- In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India read with Section 122 and Section 128 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Mediation Rules, 2016, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-IV, dated 12th August, 2022 as required by Section 122 of the said Code, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 27, in sub-rule (1), for the table, the following table shall be substituted, namely :-

TABLE

| S.No. (1) | Nature of case (2) | Honorarium (3) |
|--------------|--|--|
| 1. | On Settlement through Meditation | Rs. 5,000/- per case |
| 2. | Connected Cases | Rs. 1,000/- per case subject to a Maximum of Rs. 3,000/- (regardless of the number of connected cases) |
| 3. | In case of no Settlement (in case the party fail to arrive at an amicable settlement despite three effective hearings) | Rs. 2,500/- |

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

क्र. डी-2456.-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 477 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अध्याय बारह में, नियम 329 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“329 क इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का तेज एवं सुरक्षित प्रेषण (फास्टर) :

समस्त न्यायालयों के अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों तथा कार्यवाहियों के अभिलेखों की इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का तेज एवं सुरक्षित प्रेषण (फास्टर) प्रणाली के माध्यम से प्रेषित ई-प्रमाणीकृत प्रतियां, सभी कर्तव्य धारकों द्वारा उनमें अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुपालन और उनके सम्यक् निष्पादन के लिए विधिमान्य होंगी.”

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 28th October 2022

No.D-2456.- In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with Section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal) namely :

AMENDMENT

In the said rules, in Chapter XII, after rule 329, the following rule shall be inserted, namely :-

“329 A. Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) :

The e-authenticated copies of all the interim orders, stay orders, bail orders and record of proceedings of all the Courts transmitted through Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) system shall be valid for compliance of the directions contained therein and due execution thereof by all the duty holders.”

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

क्र. डी-2456.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 122 तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अध्याय उन्तीस में, नियम 593 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“593 क इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का तेज एवं सुरक्षित प्रेषण (फास्टर) :

समस्त न्यायालयों के अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों तथा कार्यवाहियों के अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का तेज एवं सुरक्षित प्रेषण (फास्टर) प्रणाली के माध्यम से प्रेषित ई-प्रमाणीकृत प्रतियां, सभी कर्तव्य धारकों द्वारा उनमें अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुपालन और उनके सम्यक् निष्पादन के लिए विधिमान्य होंगी.”

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 28th October 2022

No.D-2456.- In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908) and Section 23 of the Madhya Pradesh, Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in Chapter XXIX, after rule 593, the following rule shall be inserted, namely :-

“593 A. Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) :

The e-authenticated copies of all the interim orders, stay orders, bail orders and record of proceedings of all the Courts transmitted through Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) system shall be valid for compliance of the direction contained therein and due execution thereof by all the duty holders.”

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.